

राजीव भल्ला से पहले, जे.  
राजिंदर पार्टप गर्ग, - याचिकाकर्ता  
बनाम  
एच. एस. रंधावा, - उत्तरदाता  
गंभीर समीक्षा सं। 2005 का 303  
10 अक्टूबर, 2006

भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा 420 - याचिकाकर्ता व्यापार में भागीदार के रूप में प्रतिवादी शामिल होने में विफल- बेईमान खरीद-बड़े झूठी याचिका पर याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा भुगतान की गई रकम/ वादा - ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्डिंग के बाद धारा 420 आईपीसी का आरोप लगाया प्री-चार्ज साक्ष्य - चैलेंज - विशिष्ट और स्पष्ट आरोप है कि प्रतिवादी पैसे के साथ बेईमानी से भाग लेने में प्रेरित किया गया था- आरोपों के निर्धारण के चरण में गंभीर रूप से इसकी कीमत या विश्वसनीयता का विश्लेषण करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री के मूल्यांकन पर अदालत नहीं चलती है - शिकायत और साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद पारित किए गए ट्रायल कोर्ट के आरोपों का आदेश किसी भी क्षेत्राधिकार या कानून त्रुटि से ग्रस्त नहीं है - याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित, वर्तमान मामले के तथ्यों का एक खंडन प्रकट करता है विशिष्ट और स्पष्ट आरोप जो धोखा देने का अपराध की सामग्री को पूरा करते हैं। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से इसमें निवेदन किया है कि वह बेईमानी से याचिकाकर्ता द्वारा पैसे के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित, बेईमान मुनाफे में हिस्सेदारी और अंततः शिकायतकर्ता को साझेदारी व्यवसाय में शामिल करें एक वादा किया जा रहा है। प्रतिवादी, विश्वास करके याचिकाकर्ता को पैसे की रकम को सौंपना शुरू कर दिया। हालांकि, कुछ पैसे और ब्याज भी चुकाया गया था। 15 लाख वापस नहीं किया गया था। मेरे विचार में, तथ्यों के मूल्यांकन के बाद यह इस स्तर पर अभिनिर्धारित नहीं किया गया कि धारा 420 आईपीसी के तहत कोई अपराध दंडनीय नहीं है। शिकायत में दिए गए तथ्यों के मद्देनजर और सबूतों में खुलासा करने वालों ने ट्रायल कोर्ट ने सही तरीके से याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया।

(पैरा 16)

आगे अभिनिर्धारित, जहां मामले के तथ्य एक विवाद का खुलासा करते हैं, उच्च न्यायालय के लिए इस तरह की कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। वर्तमान मामले में स्थिति पूरी तरह से अलग है। शिकायत और सबूत रिकॉर्ड पर जोड़े गए तथ्यों का खुलासा करते हैं कि

अपराधिक या सिविल परिणाम को जन्म दे सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले के तथ्य एक साधारण विवाद का खुलासा करते हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्षेत्राधिकार या कानून की किसी भी त्रुटि से लगाया गया आदेश नहीं पीड़ित होना चाहिए की धारा 401 सीआर. पी.सी.के तहत क्षेत्राधिकार के अभ्यास में हस्तक्षेप किया जाए।

(पैरा 16 और 18)

संजीव बान्सल, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए*.

एस.के. वोहरा, और रूपिंदर कौर सोधि, अधिवक्ता, *प्रतिवादी के लिए*.

निर्णय

**राजीव भल्ला , जे.**

(1) इस याचिका में प्रार्थना, आदेश 25 जनवरी, 2005 को रद्द करने के लिए है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 420के तहत आरोप लगाए हैं।

(2) प्रतिवादी ने एक निजी शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया था आईपीसी की धारा 419/420 के तहत अपराध का कमीशन याचिकाकर्ता को एकमात्र आरोपी के रूप में नियुक्त किया गया था। वाईड आदेश दिनांक 23 मार्च, 2001, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ शिकायत खारिज की। प्रतिवादी द्वारा पसंद किए गए एक संशोधन को स्वीकार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा और, - वाईड आदेश दिनांक 27 नवंबर, 2001 और शिकायत, आगे की जांच के लिए मजिस्ट्रेट को दी गई। वाईड आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 2002, मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को बुलाया। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना करते हुए सम्मन आदेश को वापस बुलाने के लिए आवेदन दायर किया। आवेदन आंशिक रूप से अनुमति दी और आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया, - 8 जुलाई, 2003 को वाईड ऑर्डर। संशोधन याचिका, - वाईड आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़, द्वारा दिनांकित 17 जुलाई 2004 उपरोक्त आदेश के खिलाफ खारिज कर दिया गया था।

(3) इसके बाद, प्रतिवादी पूर्व प्रभार का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा। पूर्व-प्रभारी साक्ष्य के समापन पर और सुनवाई के बाद दोनों पक्षों द्वारा संबोधित तर्क, परीक्षण न्यायालय, - वाईड 25 जनवरी, 2005 के आदेश, धारा 420 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए, जिसके विषय में वर्तमान याचिका

(4) याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि लगाए गए आदेश आवेदन का खुलासा नहीं करते हैं, तथ्यात्मक से पीड़ित हैं त्रुटियों और मुख्य रूप से कुछ पर निर्भरता रखकर पारित किया गया है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा की गई टिप्पणियों में उसका आदेश, ताजा जांच के लिए शिकायत को दूर करते हैं।

(5) यह माना जाता है कि आरोपों के अनुसार भी इसमें धन लेनदेन लगाया गया है। 8 अप्रैल, 1985 से 14 अप्रैल, 1994 तक, जबकि शिकायत 10 मई, 2000को दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को खो दिया कि संज्ञान शिकायत को सीमा से रोक दिया गया था।

(6) यह तर्क दिया जाता है कि शिकायत में मामला दर्ज किया गया है और जैसा कि साक्ष्य से जोड़ा गया है, के लिए पैसा और विवाद का दावा है। शिकायत में आरोप उस पैसे को झूठे प्रलोभन द्वारा उन्नत किया गया था। शिकायत और साक्ष्य आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध की सामग्री का खुलासा जोड़ नहीं रहे हैं। प्री-चार्ज साक्ष्य के दौरान किसी भी परिस्थिति को निवेदन या रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है, जिससे बेईमानी का अनुमान लगाया जा सकेगा या धोखाधड़ी का इरादा, उस समय याचिकाकर्ता को कथित रूप से प्राप्त हुआ। शिकायत में आरोप लगाया गया, कि प्रतिवादी एक साझेदारी की पेशकश की और बेईमान खरीद द्वारा धोखा दिया, प्रतिवादी को शामिल करने के लिए एक भागीदार के रूप में याचिकाकर्ता की विफलता, से आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता।

(7) यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने देय धन का भुगतान ब्याज के साथ किया है और कोई बकाया रहा है, विवाद विशुद्ध रूप से सिविल है, परीक्षण न्यायालय ने चार्ज फ्रेमिंग में गलती की है।

(8) इस प्रकार, संक्षेप में, याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि शिकायत और साक्ष्य के रूप में विवाद का खुलासा, मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **अनिल महाजन बनाम भोर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और दूसरा (1) तथा मेडचेल रसायन और फार्मा (पी) लिमिटेड. बनाम जैविक ई. लिमिटेड. और अन्य (2)**

—(1)— (2005) 10 एस.सी. 228

(2) (2000) ३ एस.सी.सी. 269

(9) दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने शिकायत का एक खंडन, तथ्यों और सबूतों की दलील दी, याचिकाकर्ता द्वारा जोड़ा गया एक व्यवस्थित योजना उसके पैसे का प्रतिवादी को विभाजित करने के लिए प्रकट करता है। पेशकश की खरीद में एक हिस्सा था लाभ और व्यवसाय में एक भागीदार के रूप में था। इस बात का विरोध किया कि वादे के अनुसार कभी कोई अपराध नहीं हुआ। प्रतिवादी विस्तृत द्वारा स्थापित करने में सक्षम है कि लगातार सबूतों से कि बड़ी रकम प्रतिवादी से याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त की थी। प्रतिवादी को बेईमानी से धन की रकम के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था, एक झूठे वादे पर कि उसे साझेदारी में शामिल किया जाएगा। एक और बेईमान खरीद की पेशकश की थी। पैसे का एक बड़ा हिस्सा कभी वापस नहीं आया और प्रतिवादी को साझेदारी में शामिल नहीं किया गया था, न ही उसे भुगतान किया गया था इस प्रकार, मुनाफे का एक हिस्सा, एक बेईमान के एक अनुमान के लिए अग्रणी है लेन-देन की शुरुआत में इरादा, अर्थात्; वह समय जब याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को अपने पैसे के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

(10) यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि, पैसे वापस करने में विफलता तथ्यों में से एक है, एक शिकायत में औसत, इस तथ्य को अलगाव में पढ़ा नहीं जा सकता है कि यह शिकायत एक सिविल विवाद का खुलासा करती है। तथ्य यह है कि स्थापना के समय याचिकाकर्ताओं ने बेईमानी से उत्पीड़न किया लेन-देन के कारण, प्रतिवादी को विश्वास हो गया कि यदि उसने याचिकाकर्ता को उसका पैसा सौंपा है, वह प्रतिवादी को एक भागीदार के रूप में शामिल करेगा या मुनाफे का एक हिस्सा भुगतान करते हैं, आयोग को अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि आईपीसी की धारा 415 और 420 के तहत परिभाषित धोखाधड़ी का अपराध बनता है।

(11) यह आगे कहा गया है कि 1985 से वर्ष 2000 की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को बड़ी रकम का धोखा दिया, जैसा कि शिकायत और प्रतिवादी(ओं) के बयान में विस्तृत है और इसलिए, याचिकाकर्ता यह मानने में न्यायसंगत नहीं है कि विवाद प्रकृति में सिविल है, कोई अपराध नहीं किया गया।

(12) मैंने पार्टियों के वकील को सुना और कागज़ की किताब को पढ़ा।

(13) जैसा कि ऊपर देखा गया है, वर्तमान में चुनौती कार्यवाही आदेश चार्ज फ्रेमिंग के लिए है। जहां एक निजी शिकायत दायर किया गया है और एक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एक वारंट है, धारा 246 Cr.P.C. के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पूर्वोक्त प्रावधान एक मजिस्ट्रेट को अधिकार देता है, एक अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को फ्रेम करने के लिए, पूर्व-प्रभारी साक्ष्य के समापन पर या मामले के किसी भी पिछले चरण, बशर्ते, वह एक राय बनाता है आरोपी ने जो अपराध किया है, उसे मानने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है, जिसके लिए उसे पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है। यह तय किया गया कि एक चार्ज एक सूत्रीकरण है एक अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट अधिग्रहण है। *प्रथम दृष्टया* कि अभियुक्त ने अपराध किया, जिसके लिए उसे दंड दिया जाना चाहिए। चार्ज फ्रेमिंग के चरण में, मजिस्ट्रेट सामग्री के मूल्यांकन पर जोर देता है एक सीमित उद्देश्य के लिए, अर्थात्; पर सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए रिकॉर्ड, ताकि एक *प्रथम दृष्टया* बनाने के लिए कि एक अपराध के लिए वह आरोपी हो सकता है। एक न्यायालय, पर फ्रेमिंग चार्ज का चरण साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करता है, इसके निर्धारण के लिए शुद्धता, विश्वसनीयता या मूल्य, इसकी वैधता है। यह केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए सबूत का वजन करता है कि क्या चार्ज फरेमिंग के लिए पर्याप्त सबूत है। यहां तक कि एक मजबूत संदेह फ्रेम चार्ज के लिए पर्याप्त हो सकता है।

(14) शिकायत और सबूत के एक अनुमान के बाद ट्रायल कोर्ट, – दिनांकित आदेश के अनुसार 25 जनवरी, 2005 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 पर आरोप लगाए। पहला विवाद उठाया, अर्थात्; उस शिकायत का संज्ञान सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोपित किया गया है। धारा 468 अपराधिक प्रक्रिया संहिता, जो सीमा की अवधि निर्धारित करती है, इसके बाद संज्ञान वर्जित है, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार, उपर्युक्त विवाद, जैसा कि कानून की एक गलत धारणा पर आधारित है, खारिज कर दिया जाता है।

(15) अगला विवाद, शिकायत का एक अनुमान और रिकॉर्ड पर सबूत किसी भी अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करता है, आईपीसी की धारा 415 और धारा 420 के तहत दंडनीय है, योग्यता की स्वीकृति नहीं देता है। आरोपों को सुलझाने के चरण में और जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक न्यायालय सामग्री को गंभीर रूप से इसके मूल्य, या विश्वसनीयता का विश्लेषण करने के मूल्यांकन पर नहीं चलता है। शिकायत और मूल्यांकन के बाद परीक्षण न्यायालय सबूत, निष्कर्ष पर पहुंचे कि रिकॉर्ड पर सामग्री

पर्याप्त, फ्रेम चार्ज करने के लिए होनी चाहिए। उपर्युक्त खोज, मेरी राय में, अधिकार या कानून क्षेत्र की किसी भी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। जैसा कि संशोधन की आवश्यकता होगी, संशोधन के अभ्यास में अधिकार क्षेत्र है। यह सच है कि एक शिकायतकर्ता, मुकदमा चलाने की मांग करते हुए एक आरोपी, आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए, आरोप की स्थापना, स्पष्ट और विश्वसनीय सबूतों से की जानी चाहिए, पर वह वर्तमान मामले में बेईमानी से संपत्ति के साथ साझेदारी करने के लिए प्रेरित किया पैसा, एक बेईमान और धोखेबाज इरादे से लिया, मौजूद नहीं है। चाहे कानून में या वास्तव में, कोई भी सिद्धांत आरोपी के लिए या उसके खिलाफ एक स्वचालित निष्कर्ष नहीं निकालता, वो भी एक बेईमान इरादे को रख कर। इरादा, आम तौर पर एक अनुमान है, किसी विशेष मामले की तथ्यों और परिस्थितियों से लिया गया है।

(16) वर्तमान मामले के तथ्यों का एक खंडन, विशिष्ट और स्पष्ट आरोप को प्रकट करता है, मेरी राय में, धोखा देने का अपराध को पूरा करते हैं। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से इसमें निवेदन किया है कि वह बेईमानी से याचिकाकर्ता द्वारा पैसे के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित, बेईमान मुनाफे में हिस्सेदारी और अंततः शिकायतकर्ता को साझेदारी व्यवसाय में शामिल करें एक वादा किया जा रहा है। प्रतिवादी, विश्वास करके याचिकाकर्ता को पैसे की रकम को सौंपना शुरू कर दिया। हालांकि, कुछ पैसे और ब्याज भी चुकाया गया था। 15 लाख वापस नहीं किया गया था। मेरे विचार में, तथ्यों के मूल्यांकन के बाद यह इस स्तर पर अभिनिर्धारित नहीं किया गया कि धारा 420 आईपीसी के तहत कोई अपराध दंडनीय नहीं है। शिकायत में दिए गए तथ्यों के मददेनजर और सबूतों में खुलासा करने वालों ने ट्रायल कोर्ट ने सही तरीके से याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह दावा करने के लिए कि शिकायत का खुलासा कि यह एक सिविल विवाद है, आरोपों को हटाया नहीं जा सकता है, वर्तमान मामले के तथ्यों के रूप में एक मात्र सिविल का खुलासा नहीं करते हैं। तथ्यों का एक सेट, सिविल और / या आपराधिक दोनों को जन्म दे सकता है। जहां मामले के तथ्य, एक सिविल विवाद का खुलासा करते हैं, उच्च न्यायालय के लिए इस तरह की कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। वर्तमान मामले में स्थिति पूरी तरह से अलग है। शिकायत और रिकॉर्ड, तथ्यों और सबूत सिविल और / या आपराधिक दोनों परिणामों के लिए नेतृत्व कर सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया विवाद, वर्तमान को साधारण सिविल विवाद का खुलासा, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(एस.एस. निज्जर, ए.सी.जे.)

(17) परीक्षण न्यायालय ने एक अन्य विवाद उठाया कि, जबकि चार्ज फ्रेमिंग आदेश पर निर्भर करता है, द्वारा पारित किया गया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़, जिसके तहत शिकायत को आगे की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया था और इसलिए, स्वतंत्र दिमाग लागू करने की विफलता का खुलासे को स्वीकृति नहीं देता है। ट्रायल कोर्ट ने केवल पूर्वोक्त आदेश का उल्लेख किया, जैसा कि एक उदाहरण यह सुझाव देने के लिए कि रिकॉर्ड पर याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्ज फ्रेम की सामग्री पर्याप्त थी।

(18) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लगाया गया आदेश, है। क्षेत्राधिकार या कानून की किसी भी त्रुटि से लगाया गया आदेश नहीं पीड़ित होना चाहिए की धारा 401 सीआर. पी.सी.के तहत क्षेत्राधिकार के अभ्यास में हस्तक्षेप किया जाए। उसे देखते हुए वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अवलोकन इस क्रम में विवाद के गुणों को छूएगा नहीं तो राय की अभिव्यक्ति माना जाता है।

आर. एन. आर.

एस. एस. निज्जर, ए. सी। जे। और एस. एस. सरोन, जे.जे. के समक्ष  
मोहीनदर सिंह, - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और & अन्य, - उत्तरदाताओं  
सी. वाई. 2005 की संख्या 6099

12 अक्टूबर, 2006

. भारत का संविधान, 1950 कला. 226 - पंजाब सिविल सेवा  
(ई.बी.) नियम, 1930-- (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है) - R1.3 - पंजाब सिविल सेवा (KB) हरियाणा संशोधन नियम, 2002 - R1.9-- 13 मई, 2005 को हरियाणा राज्य द्वारा जारी अधिसूचना -याचिकाकर्ताओं का चयन एच.सी.एस. (ई.बी.) --- नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए पर चुनाव के रूप में मॉडल आचार संहिता के प्रवर्तन का खाता चुनाव आयोग चुनौती द्वारा घोषित - के दौरान याचिकाओं की पेंडेंसी. सरकार। जारी करके कैंडर की ताकत कम करना 1930 के नियमों की एक अधिसूचना - M.3 (2) सरकार को प्रदान करती है। पर होगा हर 3 साल के अंतराल में कैंडर की ताकत और संरचना की फिर से जांच की

जाती है और इसमें इस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं क्योंकि यह फिट है - क्या कैंडर की ताकत 3 से पहले फिर से निर्धारित नहीं की जा सकती थी।

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer )

करनाल, हरियाणा